मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1452

10 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति

1452. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) मध्य प्रदेश विशेष रूप से खंडवा संसदीय क्षेत्र में एससीएम के अंतर्गत कितने शहरों का उन्नयन किया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा निकट भविष्य में एससीएम को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की शुरुआत की। जनवरी, 2016 से जून, 2018 तक चार दौर के चयन के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन पूरा कर लिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में, 7 शहरों अर्थात भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चुना गया है। मिशन के तहत खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी शहर का चयन नहीं किया गया है।

21 जनवरी 2022 तक, भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए ₹28,413.60 करोड़ जारी किए हैं, जिनमें से ₹23,668.27 करोड़ (83%) का उपयोग किया जा चुका है। अब तक, इन

स्मार्ट शहरों ने ₹1,88,506 करोड़ की 6,721 परियोजनाओं का टेंडर किया है; ₹1,62,908 करोड़ की 6,124 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए हैं; ₹58,735 करोड़ की 3,421 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

शहर के स्तर पर एससीएम का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर, मिशन कार्यान्वयन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एच पी एस सी) द्वारा समन्वित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, एससीएम के कार्यान्वयन की निगरानी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा की जाती है। एसपीवी के बोर्ड में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नामित निदेशक नियमित आधार पर संबंधित शहरों में प्रगति की निगरानी करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरों के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें सुधारने के लिए विभिन्न स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं आदि के माध्यम से राज्यों/स्मार्ट शहरों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। स्मार्ट सिटी का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन और धन का उपयोग शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एससीएम के कार्यान्वयन की अवधि को भी जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है और सभी स्मार्ट शहरों को निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है।